



ना तो शार्क, ना बैराकूडा और ना ही टूना फिश, इनमें से कोई भी समुद्र की सबसे खतरनाक प्रजाति नहीं है। समुद्र के सबसे अधिक प्राणघातक जंतु हैं "सी हॉर्स"। आश्चर्यजनक रूप से सी हॉर्स बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। इनकी हरकतों को देखकर तो लगता है मानो ये बेहद मासूम और सीधे सादे हैं, इनसे कोई हानि नहीं हो सकती। जब ये तैरते हैं तो लगता है मानो कोई "मूवमेंट" ही नहीं कर रहे, पानी के प्रवाह के साथ बहते या उतरते नजर आते हैं। पर इनकी यही धीमी चाल इनके बहुत काम आती है। चुपचाप अपने शिकार तक पहुँच जाते हैं और आसानी से उसे दबोच लेते हैं, शिकार को खतरे का एहसास तक नहीं हो पाता। समुद्र के एक और नरहें जीव "कोप पॉइस" बहुत तेज गति से तैरते हैं और परभक्षियों से बच निकलते हैं पर सी हॉर्स से बचना नामुमकिन होता है क्योंकि ये इतनी धीरे-धीरे मूव करते हैं कि पानी में कोई हलचल तक नहीं होती। सी हॉर्स एकदम निकट पहुँच कर अचानक अपना सिर झटक कर कोपपॉइस को मुँह में दबोच लेते हैं। सी हॉर्स की यह टैक्नीक 90 प्रतिशत बार सफल होती है, इसी लिए ये समुद्र के सबसे खतरनाक परभक्षियों में से एक माने जाते हैं।

कांग्रेस का चतुर दांव, संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पेश करने की मांग की

अब अगर केन्द्र सरकार बिल पेश करती है तो, श्रेय कांग्रेस को मिलेगा। अगर केन्द्र सरकार बिल पेश नहीं करती है तो कांग्रेस भाजपा को कटघरे में खड़ा कर सकती है

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 सितम्बर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में कांग्रेस ग्रुप के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को अपने-अपने सदनों में महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिये दबाव बनाया। इनकी नेता सोनिया गांधी इस विधेयक को लाने के लिये लोकसभा में कई बार दबाव बना चुकी हैं।

यह विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया था लेकिन पिछले वर्षों में इसे लोकसभा में नहीं लाया गया। कांग्रेस ने कहा, "हम देश की जनता की तरफ से माँग करते हैं कि यह विधेयक सोमवार से शुरू हुये इस विशेष सत्र में लाया जाये।"

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अपनाई गई विभिन्न नीतियों का जिक्र किया तथा कहा कि, सत्तारूढ़ भाजपा "बड़ी कुर्बानी एवं कठिनाई के बाद अर्जित किये गये संवैधानिक

गौरतलब है कि, महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका, पर लोकसभा में अभी तक पेश नहीं हुआ है।

जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला यू.पी.ए. गठबंधन सत्तारूढ़ था तब पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग की।

संसद के विशेष सत्र के एजेंडा को लेकर कई अटकलें चल रही थीं, इनमें से एक यह भी थी कि, विपक्ष को मात देने और महिला मतदाताओं की सहानुभूति हासिल करने के लिए भाजपा की केन्द्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है।

मूल्यों को नष्ट करने पर तुली हुई है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल से कहा कि वह अपना ध्यान देश की हालत को सुधारने, सहानुभूति दिखाने तथा रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के महत्व पर दे। उन्होंने अपने राज्यसभा सम्मोचन में केन्द्र और भाजपा पर जमकर प्रहार किये।

खड़गे ने कहा, नेहरू का मानना था कि, सशक्त विपक्ष के न होने का मतलब है- कि प्रमाली में महत्वपूर्ण कमियाँ हैं। उन्होंने अपने पहले मंत्रिमंडल में कांग्रेस से बाहर के पांच नेता शामिल किये थे, और एक यह मोदी सरकार है, जो प्रवर्तन निदेशालय तथा सी.बी.आई. के जरिये विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है। अधीर रंजन चौधरी ने भी नेहरू के शासनकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संसद और सरकार के (शेष पृष्ठ 4 पर)

'भाजपा सनातन धर्म का मुद्दा मूल मसलों से ध्यान हटाने के लिए उछाल रही है'

राहुल ने यह कहते हुए नसीहत दी कि, कांग्रेस को भाजपा की इस चाल में नहीं फंसना है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 सितम्बर। नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) की हैदराबाद में हुई पहली मीटिंग 17 सितम्बर को समाप्त हो गई। सी.डब्ल्यू.सी. ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली

- भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडा का जवाब देने के प्रयास में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जात आधारित जनगणना करवाने की मांग उठाई।
- सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनकी चुनाव तैयारी पर भी फोकस किया गया।

भाजपा सरकार के "तानाशाही शासन" को उखाड़ फेंकने के लिये एकजुट हो जायें तथा देश में एक वैकल्पिक सरकार के लिये पूरी मेहनत से काम करें।

16 सितम्बर को शुरू हुई इस मीटिंग में दो दिन तक देश की मौजूदा स्थिति और तैयारियों का जायजा लेते हुए वैचारिक एवं चुनावी मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

सी.डब्ल्यू.सी. ने पाँच राज्यों में जल्दी ही होने वाले विधानसभा चुनावों तथा लोकसभा चुनावों के लिये संगठन की तैयारी तथा तत्परता का जायजा लिया। जहाँ देश की इस सबसे पुरानी पार्टी "इंडियन नेशनल डवलपमेंटल

इन्क्लूसिव अलार्जंस (आई.एन.डी.आई.ए- इंडिया) के "निरंतर एकीकरण" एवं दृढ़ीकरण का स्वागत किया तथा इसे "सैद्धांतिक एवं चुनावी सफलता" में तब्दील करने का संकल्प लिया। वहीं, सी.डब्ल्यू.सी. ने इस बात को रेखांकित भी किया कि विपक्षी गठबंधन से प्रधानमंत्री एवं भाजपा घबरा गये हैं।

बैठक में पारित प्रस्तावों में साफ तौर पर कहा गया, "सी.डब्ल्यू.सी. "इंडिया" को सैद्धांतिक एवं चुनावी सफलता का रूप देने के कांग्रेस पार्टी के संकल्प को दोहराती है। ताकि देश विभाजक एवं ध्रुवीकृत होती जा रही

राजनीति से मुक्त हो सके, सामाजिक निष्पक्षता एवं न्याय मजबूत हों तथा जनता को एक ऐसी केन्द्र सरकार मिले, जो जिम्मेदार, सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील तथा जवाबदेह हो।"

कांग्रेस ने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुये "सनातन धर्म" सम्बंधी बहस से स्वयं को अलग रखने का निर्णय लिया तथा यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस विवाद में नहीं पड़ेगी। कांग्रेस नेतृत्व ने यह जानते हुए इस बहस से अलग रहने का निर्णय लिया है कि, पी.एम. मोदी सहित आर.एस.एस. तथा सत्तारूढ़ पार्टी एवं उसका शीर्ष नेतृत्व, पूरी तरह चाहते हैं कि कांग्रेस उनके इस जाल में फंस जाये तथा फिर सत्तारूढ़ भाजपा उसका चुनावी फायदा ले सके।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीटिंग में शामिल प्रतिनिधियों से कहा कि, यह मुद्दा जनता के सामने मौजूद असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय (शेष पृष्ठ 4 पर)

अडानी केस में नई टीम के लिए याचिका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट में एक नया हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित मामले में ऐसी नई विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जिसमें बेदाग

- सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर्ता अनामिका जायसवाल ने मांग की है कि, मौजूदा कमेटी के कई सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए नई एक्सपर्ट टीम गठित की जाए।

ईमानदारी वाले और अडानी मामले में हितों का कोई टकराव नहीं होने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाए। यह आवेदन एक याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने पेश किया है। (शेष पृष्ठ 4 पर)

केरल और बंगाल में सीट शेयरिंग नहीं करेगी माकपा

13 सितम्बर को हुई इंडिया गठबंधन की समन्वय व प्रचार समिति की बैठक में माकपा अनुपस्थित थी

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 सितम्बर। सी.पी.एम. (माकपा) केरल एवं पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों के साथ सीट-शेयरिंग नहीं करेगी।

माना जाता है कि, सप्ताहान्त में हुई पार्टी पोलिट ब्यूरो की मीटिंग में इस आशय का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस निर्णय से, वाम पंथियों द्वारा अन्य राज्यों, जैसे बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, सीट-शेयरिंग व्यवस्था में शामिल होने की संभावना खत्म नहीं होती। बिहार में, वामपंथी गठबंधन के अन्य घटकदलों के साथ, सी.पी.एम. पहले से ही "महागठबंधन" का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन की समन्वय एवं प्रचार समिति की 13 सितम्बर को हुई मीटिंग में सी.पी.एम. का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था क्योंकि पार्टी ने इस कमेटी के लिये अपना कोई सदस्य नामजद नहीं किया था। कमेटी को इस

- माकपा के इस रुख ने कांग्रेस को दुविधा से बचा लिया है, क्योंकि प. बंगाल में तुणमूल नेता ममता बनर्जी कांग्रेस को कुछ सीटें देने के लिए मान गई थीं, पर वाम मोर्चा के लिए उन्होंने साफ इंकार कर दिया था।
- दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग करना नहीं चाहती है।
- सम्पूर्ण एकता नहीं हो पाने से इण्डिया गठबंधन की भाजपा के खिलाफ एक ही प्रत्याशी खड़ा करने की नीति प्रभावित होगी।

मीटिंग में सी.पी.एम. की सहभागिता न होने से इंडिया गठबंधन के अन्य घटकदलों, खासतौर से कांग्रेस, शर्मिन्दगी से बच गये थे। इंडिया ब्लॉक की तीसरी मीटिंग में, टी.एम.सी. प्रमुख तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि, वे 2024 के लोक चुनावों के लिये पश्चिमी बंगाल में कुछ सीटें छोड़ने के लिये तैयार हैं लेकिन सी.पी.एम. को इसमें

समायोजित नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण एकता नहीं हो पाने के कारण, भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के "वन-टु-वन" चुनावी लड़ाई के विचार पर पश्चिम बंगाल में कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता तथा पूरी एकजुटता खतरे में पड़ सकती है। वहीं केरल में इसका कोई चुनावी असर नहीं होगा क्योंकि वहाँ भाजपा की (शेष पृष्ठ 4 पर)

इस वर्ष डायरैक्ट टैक्स कलैक्शन 23.51 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली 18 सितंबर (वार्ता) चालू वित्त वर्ष में 16 सितंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.51 प्रतिशत बढ़कर 865,117 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह राशि 700416 करोड़ रुपये की तुलना में

- चालू वित्त वर्ष में 16 सितंबर तक डायरैक्ट टैक्स कलैक्शन 8,65,117 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह राशि 7,00,416 करोड़ रुपये की तुलना में 23.51 प्रतिशत अधिक है।

23.51 प्रतिशत अधिक है। आयकर विभाग ने आज यहां जारी बयान में कहा कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,65,117 करोड़ रुपये में कारपोरेट कर (सी.आई.टी.) 4,16,217 करोड़ रुपये (शेष पृष्ठ 4 पर)

अन्नाद्रमुक ने तमिलनाडू में भाजपा से गठबंधन तोड़ा

अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि, उनकी पार्टी एन.डी.ए. को छोड़ रही है, क्योंकि, भाजपा की तमिलनाडू इकाई के प्रमुख अन्नामलाई हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 सितम्बर। केन्द्र की सत्तारूढ़ भाजपा तमिलनाडू में सहयोगी संघटन का सामना कर रही है, क्योंकि उसके सहयोगी दल अन्नाद्रमुक ने घोषणा की है कि, भाजपा के साथ उसका गठबंधन नहीं है और वो एन.डी.ए. की सदस्य नहीं है। भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए अन्नाद्रमुक नेता डी. जयकुमार ने चेन्नई में घोषणा की कि, पार्टी एन.डी.ए. से बाहर है क्योंकि भाजपा के तमिलनाडू के प्रमुख के. अन्नामलाई अन्नाद्रमुक नेताओं के बारे में बकवास बातें करते हैं। तमिलनाडू से लोकसभा में 39 सांसद जाते हैं, जिनमें से अभी 38 डी.एम.के. के हैं। अब भाजपा से

अन्नाद्रमुक का अलग होना तमिलनाडू में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। तथापि, मणिपुर में गठबंधन सहयोगी के अलग होने के बाद भाजपा के लिए यह दूसरा झटका है। जयकुमार ने कहा, "भाजपा का अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन नहीं है। हम गठबंधन का निर्णय चुनाव के दौरान ही लेंगे।" उन्होंने कहा, उनकी पार्टी का यही रुख है। हालांकि भाजपा तो गठबंधन चाहती है लेकिन उसके नेता अन्नामलाई इसके खिलाफ लग रहे हैं। जयकुमार ने संवाददाताओं से कहा, "हम लगातार अपने नेताओं की आलोचना स्वीकार नहीं कर सकते। अन्नामलाई ने हमें आलोचना करने का अधिकार नहीं दे सकते। जयललिता की आलोचना कर चुके हैं। उस समय हमने अन्नामलाई के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्हें यह

- अन्नाद्रमुक नेता ने कहा, हम अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वे जयललिता के खिलाफ भी बोल चुके हैं तथा अन्नादुरै और पेरियार के बारे में भी बुरा भला कहते रहते हैं।
- तमिलनाडू में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 38 अभी द्रमुक के पास हैं।
- भाजपा को हाल ही में यह दूसरा झटका लगा है, इससे पहले मणिपुर में भी एक पार्टी ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है।

बंद कर देना चाहिए था। वे अन्ना, पेरियार और महासचिव की आलोचना कर रहे हैं, जिसे कोई कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। कल हमें जनता के बीच जाकर काम करना है। इसलिए बिना किसी विकल्प के हमने यह घोषणा कर

दी। इस निर्णय से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमें अपनी जीत का भरोसा है।" पिछले कई महीनों से भाजपा की राज्य इकाई और अन्नाद्रमुक के बीच सब सही नहीं चल रहा था और कई नेता

अन्नामलाई से नाराज हैं क्योंकि वो गठबंधन सहयोगी की कीमत पर खुद का प्रचार करना चाहते हैं। जयकुमार ने संवाददाताओं से कहा, "क्या हमें अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए? हम आपको क्यों लादे रहे? भाजपा यहां कदम नहीं रख सकती। आपका वोट बैंक सब जानते हैं। आपको यहां सब हमारी वजह से जानते हैं।" जब उनसे यह पूछा गया कि, क्या यह उनकी व्यक्तिगत राय है, तो जयकुमार ने कहा, "क्या मैंने कभी आपसे उस क्षमता में बात की है? मैं वही कहता हूँ जो पार्टी तय करती है।" अब अन्नामलाई उन अन्नादुराई की आलोचना कर रहे हैं जिन्होंने 1949 में डी.एम.के. की स्थापना की और 1967 में तमिलनाडू में पहली गैर

पहली बार प. नेहरू की तारीफ की प्र.मंत्री मोदी ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 सितंबर। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेता हमेशा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आलोचक रहे हैं, लेकिन

- मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री प. नेहरू के आजादी के अवसर पर दिए गए भाषण "ट्रिस्ट विद डैस्टिनी" का उल्लेख किया और कहा उनके भाषण की गुंज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

सोमवार को पहली बार नेहरू की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका "ट्रिस्ट विद डैस्टिनी" भाषण सांसदों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। पुराने संसद भवन में अपने अंतिम (शेष पृष्ठ 4 पर)